

प्रेषक,

एस0के0 मुददू,
अपर मुख्य सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

निदेशक,
समाज कल्याण उत्तराखण्ड,
हल्द्वानी-नैनीताल।

समाज कल्याण अनुभाग-3

देहरादून: दिनांक: 05 अगस्त, 2010

विषय: चालू वित्तीय वर्ष 2010-11 के आय-व्ययक में समाज कल्याण विभाग से सम्बन्धित अनुदान संख्या-15 के छात्रवृत्ति और छात्रवेतन में प्राविधानित धनराशि की वित्तीय स्वीकृति के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक, वित्त विभाग, उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्या: 187/XXVII(1)/2010 दिनांक 30 मार्च, 2010 की छायाप्रति संलग्न कर प्रेषित करते हुए मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि चालू वित्तीय वर्ष 2010-11 के आय-व्ययक में समाज कल्याण विभाग से सम्बन्धित अनुदान संख्या-15 की आयोजनागत पक्ष में प्राविधानित धनराशि रू0 2,25,00,000/- (रुपये दो करोड़ पच्चीस लाख मात्र) की धनराशि को चालू वित्तीय वर्ष 2010-11 में वित्त विभाग के उक्त शासनादेश एवं निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन आपके निर्वर्तन पर रखे जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

1. वित्त अनुभाग-1 के शासनादेश संख्या: 187/XXVII(1)/2010 दिनांक 30 मार्च, 2010 में उल्लिखित समस्त शर्तों एवं दिशा-निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।
2. अनुदान के अन्तर्गत होने वाले सम्भावित व्यय की फेजिंग (त्रैमास के आधार पर) अनिवार्य रूप से शासन को उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जाए, जिससे राज्य स्तर पर कैशप्लो निर्धारित किये जाने में किसी प्रकार की कठिनाई न उत्पन्न हो।
3. आय-व्यय द्वारा व्यवस्थित उक्त धनराशि में से केवल स्वीकृत चालू योजनाओं पर ही व्यय किया जाय और किसी भी दशा में उक्त धनराशि का उपयोग नये कार्यान्वयन के लिए न किया जाय।
4. उक्त आवंटित धनराशि किसी ऐसी मद पर व्यय करने से पूर्व वित्तीय हस्त पुस्तिका के अन्तर्गत शासन या अन्य सक्षम अधिकारी की पूर्व स्वीकृति आवश्यक हो तो ऐसा व्यय अपेक्षित स्वीकृति प्राप्त करके ही किया जाए।
5. यह व्यक्तिगत रूप से सुनिश्चित कर लिया जाए कि आवश्यकतानुसार आवंटित धनराशि के प्रत्येक बिल में चाहे वह वेतन आदि के संबंध में हो अथवा आकस्मिक व्यय के संबंध में, सम्पूर्ण मुख्य/लघु/उप तथा विस्तृत शीर्षक को अंकित किया जाए और प्रत्येक बिल में दाहिनी और लाल स्याही से अनुदान संख्या-15 तथा आयोजनागत शब्द स्पष्ट लिखा जाए, अन्यथा महालेखाकार, कार्यालय में सही बुकिंग में बाधा होगी।
6. मितव्ययता के सम्बन्ध में नियमों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।
7. यदि किसी अधिष्ठान/योजनाओं के अन्तर्गत अतिरिक्त धनराशि की मांग का औचित्यपूर्ण प्रस्ताव शासन को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

8. अप्रयुक्त धनराशि वित्तीय हस्त पुस्तिका के प्राविधानों के अन्तर्गत समय-सारिणी के अनुसार समर्पित किया जाना सुनिश्चित किया जाए।
9. उपर्युक्त निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन अपने एवं अधीनस्थ स्तरों पर भी सुनिश्चित करें।
10. उक्त धनराशि आपके निवर्तन पर इस शर्त एवं प्रतिबन्ध के साथ रखी जा रही है कि उक्त धनराशि का व्यय इस वर्ष मात्र नवीनीकरण छात्रवृत्ति में ही किया जाय। नई छात्रवृत्तियां केवल जैन समुदाय के पात्र छात्रों के पक्ष में स्वीकृति की जाय व शेष अल्पसंख्यक समुदाय की नई छात्रवृत्तियां केन्द्र पोषित योजना से आच्छादित की जाय, आगामी शिक्षा संघ से, जैन समुदाय के पात्र लाभार्थियों को छोड़कर, शेष सभी अल्पसंख्यक छात्रों (जैन समुदाय के छात्रों को छोड़कर) को केन्द्र पोषित योजना से आच्छादित किया जाय, जिनके लिए इस वर्ष राज्य योजना से लाभान्वित छात्रों को छात्रवृत्ति आवंटन के समय इस सत्र में न्यूनतम 50 प्रतिशत अंक प्राप्त करने पर ही आगामी सत्र में छात्रवृत्ति देय होने (केन्द्रीय योजना से) के संबंध में सूचित किये जाने की व्यवस्था सुनिश्चित कर दी जाय। राज्य योजना के अन्तर्गत आच्छादित होने वाले जैन समुदाय के लाभार्थियों हेतु भी आगामी सत्र से न्यूनतम 50 प्रतिशत प्राप्तांक के अर्हता बिन्दु को रखे जाने के संबंध में आवश्यक कार्यवाही पूर्ण की जाय।
11. बी0एम0-13 पर संकलित मासिक सूचनाएँ नियमित रूप से शासन को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।
12. इस संबंध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2010-11 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या-15 के आयोजनागत पक्ष में लेखाशीर्षक-2250-अन्य सामाजिक सेवाएं-800-अन्य व्यय-16-अल्पसंख्यक समुदाय के कक्षा 1 से 10 तक के छात्रों की छात्रवृत्ति के मानक मद 21-छात्रवृत्ति एवं छात्रवेतन के नामे डाला जाएगा।
13. यह आदेश वित्त विभाग के शासनादेश संख्या:-97(P)/XXVII(1)/2010 दिनांक 02 अगस्त, 2010 में दिये गये निर्देशों के क्रम में जारी किये जा रहे हैं।

संलग्न: यथोपरि।

भवदीय,

(एस0के0 मुद्दू)

अपर मुख्य सचिव।

पृष्ठांकन संख्या: 972 (1)/ xvii-3/2010-07(38)/2008 तददिनांक।

प्रतिलिपि : निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- निजी सचिव, मा0 मुख्यमंत्री, उत्तराखण्ड।
- 2- निजी सचिव, मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
- 3- महालेखाकार, उत्तराखण्ड, देहरादून।
- 4- मण्डलायुक्त, गढ़वाल/कुमाऊं, उत्तराखण्ड।
- 5- निदेशक, कोषागार एवं वित्त सेवाएं, उत्तराखण्ड, देहरादून।
- 6- समस्त जिला समाज कल्याण, अधिकारी, उत्तराखण्ड।
- 7- वित्त(व्यय नियंत्रण) अनुभाग-03, उत्तराखण्ड शासन।
- 8- बजट, राजकोषीय नियोजन व संसाधन नि0, सचिवालय परिसर, देहरादून।
- 9- समाज कल्याण नियोजन प्रकोष्ठ, सचिवालय परिसर, देहरादून।
- 10- राष्ट्रीय सूचना केन्द्र, उत्तराखण्ड सचिवालय परिसर, देहरादून।
- 11- आदेश पंजिका।

आज्ञा से,

(आर0 के0 चौहान)

अनु सचिव।